भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1949

(जिसका उत्तर सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया)

कंपनियों के स्वैच्छिक समापन के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कारपोरेट एग्जिट (सी-पेस)

1949. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री भोला सिंहः

डॉ. सुकान्त मजूमदारः

श्री विनोद कुमार सोनकरः

श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों के स्वैच्छिक समापन को सुविधाजनक बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कारपोरेट एग्जिट (सीपेस) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी-सिटी) में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना और विदेशी विश्वविद्यालयों को कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सीमा-पार दिवाला सहित समाधान प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कंपनियों के स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया को छह महीने तक कम करने के लिए कोई केंद्र स्थापित करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क), (घ) और (ङ):- जी, हाँ। स्टेकहोल्डरों को व्यवसाय से एक्जिट करने में सुगमता प्रदान करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कारपोरेट एक्जिट (सी-पेस) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्तावित है कि सी-पेस छह महीने के अंदर स्वैच्छिक आधार पर कंपनियों के एग्जिट के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत ई-फॉर्म एसटीके-2 के माध्यम से फाइल किए गए सभी आवेदनों को केंद्रीय रूप से संसाधित करने और उन्हें अनुमोदित करने का प्रयास करेगा।

(ख): जी, हाँ। माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2022-23 में, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करने और वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए अत्यधिक उच्च गुणवत्तायुक्त मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए आईएफएससीए द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रमों के सिवाय विदेशी विश्वविद्यालयों को घरेलू विनियमों से मुक्त वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करने की अनुमति देने की घोषणा की है।

(ग): सचिव, एमसीए की अध्यक्षता में दिवाला विधि समिति (आईएलसी), दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर सरकार को सिफारिशें प्रदान करती है। स्टेकहोल्डरों के परामर्श और सरकार द्वारा की गई जांच के साथ आईएलसी की सिफारिशों के आधार पर, उत्पन्न होने वाली अपेक्षाओं के अनुसार संहिता में संशोधन किए जाते हैं।

*****